Date – 29 July 2022

मानव-वन्यजीव संघर्ष

- हाल ही में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष

- मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) उन संघर्षों को संदर्भित करता है जब वन्यजीवों की उपस्थिति या व्यवहार मानव हितों या जरूरतों के लिए वास्तविक या प्रत्यक्ष खतरे का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों, जानवरों, संसाधनों और आवास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कारण:

- प्राकृतिक वास का नुकसान।

- जंगली जानवरों की आबादी में वृद्धि।
- फसल के पैटर्न में बदलाव जो जंगली जानवरों को खेत की ओर आकर्षित करते हैं।
- भोजन और चारे के लिए जंगली जानवरों का वन क्षेत्र से मानव-बहुल क्षेत्रों में आना-जाना।
- वनोपज के अवैध संग्रहण के लिए मनुष्यों का वनों की ओर आना-जाना।
- आक्रामक विदेशी प्रजातियों आदि की वृद्धि के कारण आवास का क्षरण।

प्रभाव:

- जीवन खोना।
- जानवरों और मनुष्यों दोनों को चोट लगना।
- फसलों और कृषि भूमि को नुकसान।
- जानवरों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि।

संबंधित डेटा:

- 2018-19 और 2020-21 के बीच देश भर में 222 हाथियों की करंट लगने से मौत हो गई।
- इसके अलावा वर्ष 2019 से 2021 के बीच 29 बाघों की अवैध शिकार से मौत हुई, जबकि 197 बाघों की मौत की जांच की जा रही है.
- मानव-से-पशु संघर्षों के दौरान हाथियों ने तीन वर्षों में 1,579 मनुष्यों की हत्या की – 2019-20 में 585, 2020-21 में 461 और 2021-22 में 533।
- 332 मौतों के साथ ओडिशा सबसे ऊपर है, इसके बाद 291 के साथ झारखंड और 240 के साथ पश्चिम बंगाल है।
- जबकि 2019 से 2021 के बीच बाघों ने रिजर्व में 125 इंसानों को मार डाला।
- इनमें से लगभग आधी मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं।

संघर्ष से निपटने के लिए की गई पहल:

मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) के प्रबंधन के लिए सलाह:

- यह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (SC-NBWL) की स्थायी समिति द्वारा जारी किया जाता है।

ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना:

- एडवाइजरी में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार समस्याग्रस्त जंगली जानवरों से निपटने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है।

बीमा प्रदान करना:

- एचडब्ल्यूसी के कारण फसल क्षति के मुआवजे के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऐड-ऑन कवरेज का उपयोग करना।

बढ़ता चारा:

- वन क्षेत्रों के भीतर चारा और जल स्रोतों को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

सक्रिय उपाय करना:

- स्थानीय/राज्य स्तर पर अंतर-विभागीय समितियों को निर्धारित करना, पूर्व चेतावनी प्रणाली को अपनाना, बाधाओं का निर्माण, टोल-फ्री हॉटलाइन नंबरों के साथ समर्पित सर्कल-वार नियंत्रण कक्ष, हॉटस्पॉट की पहचान आदि।

तत्काल राहत प्रदान करना:

- घटना के 24 घंटे के भीतर पीड़ित/परिवार को अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि के एक हिस्से का भुगतान।

स्वदीप कुमार

फ्रीबीज़

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या चुनाव अभियानों के दौरान तर्कहीन फ्रीबीज़ (मुफ्त उपहार) वितरित करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।
- इसने तर्कहीन चुनावी मुफ्तखोरी पर अंकुश लगाने में वित्त आयोग की विशेषज्ञता के उपयोग का भी उल्लेख किया।

- भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, क्या ऐसी नीतियां आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं या राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, यह राज्य के मतदाताओं के लिए विचार करने और निर्णय लेने का प्रश्न है।

फ्रीबीज़

- राजनीतिक दल लोगों का वोट सुरक्षित करने के लिए मुफ्त बिजली/पानी की आपूर्ति, बेरोजगारों, दिहाड़ी मजदूरों और महिलाओं को भत्ता, साथ ही लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि जैसे गैजेट देने का वादा करते हैं।
- राज्यों को मुफ्त बिजली, साइकिल, लैपटॉप, टीवी सेट आदि के रूप में कर्जमाफी या मुफ्त उपहार देने की आदत हो गई है।
- लोकलुभावन वादों या इनमें से कुछ खर्चों पर, निश्चित रूप से चुनावों को ध्यान में रखते हुए, निश्चित रूप से सवाल उठाए जा सकते हैं।
- लेकिन यह देखते हुए कि पिछले 30 वर्षों से देश में असमानता बढ़ रही है, सब्सिडी के रूप में आम आबादी को किसी भी तरह की राहत देना अनुचित नहीं माना जा सकता है, लेकिन वास्तव में अर्थव्यवस्था के लिए विकास पर बने रहना आवश्यक है।

फ्रीबीज़ की जरूरत:

विकास की सुविधा:

- ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि कुछ व्यय परिव्यय के समग्र लाभ के रूप में है जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजनाएं, और विशेष रूप से महामारी के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सहायता।

अविकसित राज्यों को सहायता:

- गरीबी से पीड़ित आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर के विकास वाले राज्यों में आवश्यकता/मांग के आधार पर ऐसी मुफ्त सुविधाएं हैं और उन्हें ऊपर उठाने के लिए, उन्हें सब्सिडी प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है।

अपेक्षाओं की पूर्ति:

- भारत जैसे देश में जहां राज्यों में विकास का एक निश्चित स्तर है (या नहीं है), लोगों की उम्मीदें चुनाव के अवसर पर किए गए लोकलुभावन वादों से पूरी होती हैं।

मुफ्त की कमियां:

वृहद अर्थव्यवस्था के लिए अस्थिर:

- फ्रीबीज मैक्रोइकॉनॉमी की स्थिरता के बुनियादी ढांचे को कमजोर करता है, फ्रीबीज की राजनीति खर्च प्राथमिकताओं को विकृत करती है, और परिव्यय किसी न किसी रूप में सब्सिडी पर केंद्रित होता है।

राज्यों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव:

- मुफ्त उपहार देने से अंततः राजकोष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भारत के अधिकांश राज्यों में मजबूत वित्तीय प्रणाली नहीं है, अक्सर राजस्व के मामले में बहुत सीमित संसाधनों के साथ।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ:

- मुफ्त सार्वजनिक धन के तर्कहीन पूर्व-चुनाव वादे मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करते हैं, सभी के लिए समान अवसर की स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं, और चुनाव प्रक्रिया की अखंडता को नष्ट करते हैं।

पर्यावरण से दूर:

- जब मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है, तो इससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होगा और अक्षय ऊर्जा प्रणालियों से ध्यान भी भटकेगा।

स्वदीप कुमार

INS विक्रांत नौसेना

भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और मजबूत हथियार के रूप में स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर 'विक्रांत' शामिल हो गया है। भारतीय नौसेना में शामिल होने के साथ ही भारत की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और दुश्मन इससे थर-थर कापेंगे। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले बेहद जटिल परीक्षण से गुजरा है। पिछले साल ही अगस्त में यह विमानवाहक पोत अपनी पांच दिवसीय समुद्रीय यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया था। इससे पहले पोत ने 10 दिवसीय समुद्री यात्रा पूरी की थी।

देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत (एयरक्राफ्ट कैरियर) "विक्रांत" 28 जुलाई 2022 गुरुवार को नौसना में शामिल हो गया है । कोचीन

शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने कोच्ची में इसे नौसेना के हवाले किया । 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के हिस्से के रूप में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने इसका निर्माण किया है, और नौसेना डिज़ाइन निदेशालय ने इसका डिजाईन तैयार किया है।

भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत नौसेना में शामिल

- वर्तमान में भारत के पास केवल रूसी मूल का आईएनएस विक्रमादित्य एकमात्र विमानवाहक पोत है ।

आईएनएस विक्रांत

- इस स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम नौसेना के सेवामुक्त प्रथम वाहक के नाम पर 'विक्रांत' रखा गया है।
- इसमें 30 विमानों का एक वायु घटक है, जिसमें स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों के अलावा मिग-29K लड़ाकू जेट, कामोव-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर और जल्द ही नौसेना में शामिल होने वाले MH-60R मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा सकेगी।

- इसकी अधिकतम गति तकरीबन 30 समुद्री मील (लगभग 55 किमी. प्रति घंटा) है और इसे चार गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित किया जाता है। स्वदेशी विमानवाहक एक बार में 18 समुद्री मील (32 किमी. प्रति घंटे) की गति से 7,500 समुद्री मील की दूरी तय करने में सक्षम है।
- इस विमानवाहक पर हथियारों के रूप में बराक LR SAM और AK-630 शामिल हैं, साथ ही इसमें सेंसर के रूप में MFSTAR और RAN-40 L3D रडार शामिल हैं। पोत में 'शक्ति' नाम का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी मौजूद है।
- इस विमानवाहक पोत में विमान संचालन को नियंत्रित करने के लिये 'रनवे' और 'शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टड रिकवरी' सिस्टम भी मौजूद है।
    - स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत बनाने के लगभग साढ़े चार साल के बाद भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। यह 45 हजार टन वजनी है।
    - यह काफी विशालकाय जहाज है। यह स्वदेशी युद्धपोत 262 मीटर लंबा तथा 60 मीटर चौड़ा है।
    - आईएनएस विक्रांत के लांच के साथ भारत कुछ गिने-चुने देशों की सूची में शामिल हो गया है, जो इस प्रकार के जहाज का डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम है। इस तरह के जहाजों का निर्माण करने दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ही कर पाते हैं। इस पोत के आकार और क्षमता ने भारत को नई पहचान दिलाई है।
    - यह पोत एक साथ 30 फाइटर प्लेन को अपने साथ ले जाने में सक्षम है।
    - एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत में 14 डेक यानी 14 मंजिलें हैं।

- इसको भारत में ही डिजाइन किया गया है। भारतीय स्टील आथारिटी ने इसमें सबसे अच्छी गुणवत्ता की युद्धपोत स्टील का प्रयोग किया है। इसकी स्टील इसको जबरदस्त मजबूती मिलती है।
- आईएनएस विक्रांत के लगभग 76 प्रतिशत हिस्से को भारत में ही बनाया गया है। इसके लिए डीआरडीओ और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने उच्च गुणवत्ता वाली स्टील का उपयोग किया है।
- पोत को नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है।
- जहाज कुल 88 मेगावाट बिजली की चार गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित है। इसकी अधिकतम स्पीड 28 नाटिकल मील है।
- इसको बनाने में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की लागत आई है।

आईएनएस विक्रांत महत्त्व:

- एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के पहले समुद्री परीक्षण अगस्त 2021 में सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए थे। इसके बाद अक्टूबर 2021 में दूसरे और जनवरी 2022 में तीसरे समुद्री परीक्षण भी पूरे कर लिए गए थे। विक्रांत के शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हुआ है जिससे भारत की स्थिति हिन्द महासागर में और मजबूत होगी।
- विमानवाहक पोत की लड़ाकू क्षमता, पहुँच और बहुमुखी प्रतिभा देश की रक्षा में मज़बूत क्षमताओं को जोड़ेगी और समुद्री क्षेत्र में भारत के हितों को सुरक्षित रखने में मदद करेगी।
- यह लंबी दूरी पर वायु शक्ति को प्रक्षेपित करने की क्षमता के साथ एक अतुलनीय सैन्य उपकरण की पेशकश करेगा, जिसमें हवाई अवरोध,

सतह-विरोधी युद्ध, आक्रामक और रक्षात्मक काउंटर-एयर, हवाई पनडुब्बीरोधी युद्ध तथा हवाई पूर्व चेतावनी शामिल हैं।

भारतीय नौसेना की वर्तमान स्थिति:

- **समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना** (**Maritime Capability Perspective Plan)** के अनुसार, वर्ष 2027 तक भारत के पास लगभग 200 जहाज़ होने चाहिये परंतु लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।
    - हालाँकि इसका कारण मुख्य रूप से वित्तपोषण नहीं बल्कि प्रक्रियात्मक देरी या स्वयं द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंध हैं।
- नौसेना के पास अत्याधुनिक सोनार और रडार हैं। इसके अलावा इसके कई जहाज़ों में स्वदेशी सामग्री की उच्च मात्रा इस्तेमाल की गई है।

कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में नौसेना का योगदान:

- **ऑपरेशन समुद्र सेतु- I:** कोरोना वायरस के मद्देनज़र लागू किये गए यात्रा प्रतिबंधों के बीच विदेश में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिये निकासी अभियान है।
    - यह खाड़ी युद्ध की शुरुआत में वर्ष 1990 में एयरलिफ्ट किये गए 1,77,000 लोगों की संख्या से भी आगे निकल गया है।
- इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के पोत जलश्व, ऐरावत, शार्दुल और मगर ने भाग लिया।
- **ऑपरेशन समुद्र सेतु-II**
    - इस ऑपरेशन के हिस्से के रूप में सात भारतीय नौसेना जहाज़ों अर्थात् कोलकाता, कोच्चि, तलवार, टाबर, त्रिकंड, जलश्व तथा ऐरावत को विभिन्न देशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन-फील्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स और संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट की शिपमेंट के लिये तैनात किया गया है।

- दो जहाज़ INS कोलकाता और INS तलवार, मुंबई के लिये 40 टन तरल ऑक्सीजन लाने हेतु मनामा और बहरीन के बंदरगाहों में प्रवेश कर चुके हैं।
- INS जलाश्व और INS ऐरावत भी इसी प्रकार के मिशन के साथ क्रमशः बैंकॉक और सिंगापुर के मार्ग पर हैं।

रवि सिंह